

8. How has the 86th Constitutional Amendment expanded the scope of Fundamental Duties? Discuss how the duty relating to education (Art. 51A(k)) complements the Right to Education under Article 21A.

86वें संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों के दायरे को कैसे विस्तारित किया है? अनुच्छेद 51A(k) से संबंधित शिक्षा के कर्तव्य किस प्रकार अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को पूरक बनाते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।

9. Explain the concept of 'harmonious construction' used by the judiciary to reconcile Fundamental Rights and DPSPs.

मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSPs) के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए न्यायपालिका द्वारा प्रयुक्त 'सामंजसपूर्ण व्याख्या' (Harmonious Construction) की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।

10. Write short notes on **Any Two** of the following :

निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) Objectives Resolution

उद्देश्य प्रस्ताव

- (b) Constitutional Supremacy

संवैधानिक सर्वोच्चता

- (c) Parliamentary System in India

भारत में संसदीय प्रणाली

- (d) Article 19(A)

अनुच्छेद 19(A)

(1000)

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

आपका अनुक्रमांक.....

Sr. No. of Question Paper : 13488

K

Unique Paper Code : 2324000014

Name of the Paper : FUNDAMENTAL RIGHTS, DUTIES AND DIRECTIVE PRINCIPLE OF STATE POLICY

Name of the Course : **COMMON PROG GROUP-GE**

Semester/Annual : VII

सेमेस्टर/वार्षिक

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt **Any Five** questions.
3. **All** questions carry equal marks.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. **किन्हीं पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

P.T.O.

3. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।
1. The Preamble of the Indian Constitution is a reflection of its philosophy. Comment.
“भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके दर्शन का प्रतिबिंब है।” टिप्पणी करें।
2. Critically evaluate the extent to which the constitutional mechanisms in India have succeeded in realizing the Preamble's vision of social, economic and political justice.
भारत में संवैधानिक तंत्र किस हद तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित प्रस्तावना की दृष्टि को साकार करने में सफल हुए हैं- इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
3. Explain the concept of the 'Basic Structure' of the Indian Constitution. Analyse the major elements that the Supreme Court has identified as part of the Basic Structure over the years.
भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। उन प्रमुख तत्वों का विश्लेषण कीजिए जिन्हें पिछले कुछ वर्षों के दौरान के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना का हिस्सा माना है।
4. Discuss the meaning, nature, and scope of Fundamental Rights under the Indian Constitution. How do they differ from ordinary legal rights?

- भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्राधिकार पर चर्चा कीजिए। वे साधारण विधिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न हैं?
5. Discuss Article 32 as the 'heart and soul' of the Indian Constitution with respect to constitutional remedies. How do writs under this Article function to secure justice and protect individual rights?
संवैधानिक उपचारों के संदर्भ में अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का 'हृदय और आत्मा' माना जाने पर चर्चा कीजिए। इस अनुच्छेद के तहत जारी किए जाने वाले रिट किस प्रकार न्याय सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करते हैं?
6. Examine the limitations imposed on Fundamental Rights. How does the Constitution balance individual freedoms with public interest and national security?
मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की परीक्षा कीजिए। संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किस प्रकार संतुलित करता है?
7. Explain the concept of Directive Principles of State Policy (DPSPs). How do they reflect the vision of social and economic justice in India?
राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। वे भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय की दृष्टि को किस प्रकार दर्शाते हैं?